

12.36 hrs.

**Title: Adjournment motion regarding distress sale of paddy by the farmers in Bihar.**

**MR. SPEAKER: I am giving the floor to Shri Devendra Prasad Yadav because he has given a notice for the Adjournment Motion.**

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ। आपने नियमन दिया था कि शून्य काल में मैं इस सवाल को उठा सकता हूँ। सदन के कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 56 के तहत मैंने स्थगन प्रस्ताव का एक नोटिस दिया है, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण, अविलम्बनीय और तात्कालिक लोक महत्व का विषय है। नियम 60 ए में अध्यक्ष महोदय को नियम 56 के बारे में सम्मति और असम्मति देने का अधिकार है।

मेरा विषय यह है कि सम्पूर्ण बिहार में बड़े पैमाने पर लाखों किसानों के धान की खरीद नहीं होने के कारण उनमें बड़ा भारी असंतोह है और एफ.सी.आई. के प्रति विस्फोटक स्थिति उनके अंदर पैदा हो गई है। किसान अपना धान डिस्ट्रेस सेल करने पर मजबूर हो रहे हैं। वे 200 रुपए, 250 रुपए और 300 रुपए प्रति क्विंटल अपने धान को बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इससे किसानों को लागत मूल्य भी नहीं प्राप्त हो रहा है, जबकि खेती को घाटे का व्यवसाय का दर्जा दिया गया है। पिछले साल पूरे बिहार में 123 लाख मीट्रिक टन धान का उत्पादन हुआ था। उसमें से केवल 7 हजार 636 टन धान ही की खरीद हुई है, वह भी डिस्ट्रेस सेल के आधार पर। एम.एस.पी. का लाभ बिहार में पिछले साल भी किसानों को नहीं मिला। इस साल भी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो कामन पैडी के लिए और स्पेशल ग्रेड ए के लिए क्रमशः 530 रुपए और 560 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, नहीं मिल रहा है। पूरे देश में अक्टूबर तक 3150449 टन प्रोक्योरमेंट हुई है। अकेले पंजाब में एम.एस.पी. के आधार पर 30 नवम्बर तक 97 लाख 31 हजार 248 टन पैडी की खरीद हुई है। मैं किसी राज्य की चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि दोहरी नीति, दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है? भारत सरकार इस तरह का भेदभाव बिहार के साथ क्यों कर रही है? बिहार के लाखों किसान आज जाड़े में ठिठुर रहे हैं। उनके बच्चे किताबें नहीं खरीद सकते। किसान रोजमर्रा का सामान मार्केट से नहीं ले सकते। उनका एकमात्र जरिया धान ही है, मार्केट से सामान खरीदने का। इस कारण बिहार के किसानों में हाहाकार मचा हुआ है और त्राहिमाम की स्थिति है। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए बिहार के साथ दोहरी नीति और दोहरे मापदंड को बंद किया जाए। सरकार किसान की फसल खरीदने में कुछ रिलैक्सेशन भी देती है, वहां यह भी नहीं दिया गया।<sup>1</sup> (व्यवधान) मैं बताना चाहता हूँ कि कहां-कहां प्रोक्योरमेंट शून्य है।

इस बार की खरीफ फसल 2001-2002 शुरू हो गयी है लेकिन बिहार में उसकी प्रोक्योरमेंट शून्य है, एक छटांक भी भाग धान पैडी भी नहीं खरीदी गई। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में भी प्रोक्योरमेंट शून्य है।<sup>2</sup> (व्यवधान) उड़ीसा में केवल राइस लेवी के रूप में 27,066 टन 28 नवम्बर तक खरीदा गया और कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में मोटे अनाज का प्रोक्योरमेंट शून्य है। जैसे राजस्थान में मकई है, बाजरा है, उसी तरह बिहार में महुआ है - उसके एक भी कोर्स ग्रेन का भी प्रोक्योरमेंट शुरू नहीं हुआ।<sup>3</sup> (व्यवधान) इसलिए हमारे प्रस्ताव के औचित्य को देखते हुए, कार्य संचालन नियमावली के नियम <sup>4</sup> (व्यवधान) 56 के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव रखने की अनुमति दी जाये। यदि आप इंकार करेंगे तो उसके कारण बताने की कृपा की जाये क्योंकि सब अधिकार आपको है।<sup>5</sup> (व्यवधान)

**MR. SPEAKER: I think, last week the Business Advisory Committee decided to discuss the procurement policy also. So, we are going to discuss this issue....(Interruptions)**

**श्री प्रमुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) :** अध्यक्ष महोदय, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि शून्य-काल के समय माननीय देवेन्द्र प्रसाद जी ने एक प्रस्ताव दिया था, जिस संबंध में हम सब ने आपके चेम्बर में आपसे मिल कर निवेदन भी किया था। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि यह सवाल बिहार का है। बिहार के किसानों की पीड़ा, परेशानी और दुख-दर्द के संबंध में देवेन्द्र प्रसाद जी ने चर्चा की और हमने नियमों के अनुकूल प्रस्ताव आपके समक्ष रखा है। अध्यक्ष जी, हम चाहेंगे कि हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए इस पर चर्चा कराने की कृपा करें, यही हमारा आपसे निवेदन है।

**अध्यक्ष महोदय :** ठीक है, चर्चा कराएंगे।<sup>6</sup> (व्यवधान)

**MR. SPEAKER: We will discuss the matter.**

**श्री प्रमुनाथ सिंह :** अध्यक्ष महोदय, हमने जो कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है, उस पर हम निवेदन करना चाहते हैं।<sup>7</sup> (व्यवधान)

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) :** अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री को इस पर रेस्पॉन्ड करना चाहिए। यह गंभीर मामला है।

**संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) :** अध्यक्ष जी, जब किसानों पर यहां चर्चा हुई थी तो बहुत से माननीय सदस्यों को ऐसा लगा था कि जब किसानों की चर्चा करते हैं तो धान की जो खरीद होती है वह भी किसानों की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर बहस होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से कृषि मंत्री जी उसका अलग से उत्तर नहीं दे पाते हैं। इसलिए उस दिन भी बहुत से माननीय सदस्यों की मांग थी कि धान की खरीद के विषय में अलग से चर्चा होनी चाहिए। आज देवेन्द्र प्रसाद यादव जी ने और अन्य माननीय सदस्यों ने जो विषय उठाया है इस पर चर्चा कराने में सरकार को कोई एतराज नहीं है। अगर आपकी आज्ञा हो, सदन की सहमति हो तो आने वाले सोमवार को ही इस विषय पर हम चर्चा कर सकते हैं जिसमें मंत्री जी आकर चर्चा के पश्चात् उत्तर दे सकते हैं।